नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
इंदौर 65 वां वर्ष संस्करण

4 विकसित भारत की नींव बनेंगे अमृत रेलवे स्टेशन

5 ऑपरेशन सिंदूर मोदी की इच्छाशक्ति

8 इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे पर कसा शिकंजा

9 वित्त वर्ष 2025 में भारतीय विमानन क्षेत्र ने भरी उड़ान

एक नजर में

डोनाल्ड ट्रंप पर हार्वर्ड विवि ने ठोक दिया मुकदमा

वॉशिंगटन. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच विवाद गहराता जा रहा है. ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. हार्वर्ड ने शुक्रवार को दूसरी बार मुकदमा दायर किया है. हार्वर्ड के अध्यक्ष डॉ. एलन एम. गार्बर ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया, हम इस गैरकानूनी और अनुचित कार्रवाई की निंदा करते हैं. यह हार्वर्ड के हजारों छात्रों और विद्वानों के भविष्य को खतरे में डालता है.

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली ढेर

सुकमा. छत्तीसगढ के सुकमा जिले में पुलिस-नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शुक्रवार को एक नक्सली मारा गया और इलाके में गोलीबारी जारी है. पुलिस के अनुसार जिले के किष्टाराम क्षेत्र से गुरुवार को जिला रिजर्व पुलिस बल, आर्म्स एक्ट फोर्स तथा कोबरा बटालियन के जवान नक्सली विरोधी अभियान पर निकले थे. पुलिस एवं सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल रात से रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है. जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आयी है. मुठभेड़ अभी भी जारी है.

हाई कोर्ट, सुको से ज्यादा लोकतांत्रिक : जस्टिस

नई दिल्ली. जस्टिस अभय ओका ने सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने की मांग की है. उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस केंद्रित है और इसमें बदलाव की जरूरत है. जस्टिस अभय ओका का 23 मई को एक जज के रूप में आखिरी दिन था. अपने विदाई भाषण में उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये बदलाव चीफ जस्टिस बीआर गवई कर सकते हैं. जस्टिस ओका ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं. उन्होंने कहा, हाई कोर्ट समितियों के जरिए काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पर केंद्रित है.

लॉरेंस गिरोह के प्रमुख सदस्य गिरफ्तार

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खूंखार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है जो गिरोह के सदस्यों को फर्जी पासपोर्ट की मदद से देश से भागने में मदद कर रहा था. एनआईए ने शुक्रवार को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पासपोर्ट मॉड्यूल को चलाने वाले राहुल सरकार को एजेंसी की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया.

गुस्ताखी माफ

मंत्री शाह ने फिर मांगी माफी

पिछले 10 दिन में तीसरी बार मांग चुके माफी

- अब कहा, मैं अपनी भाषाई भूल के लिए क्षमापार्थी
- सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद एक्स पर भी पोस्ट किया

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 मई. प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री ने एक बार फिर भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी सहित सभी देशवासियों से माफी मांगी है. उन्होंने पिछले दिनों दिये गये बयान को भाषाई भूल करार दिया है. उन्होंने बाकायदा लिखित में माफी मांगी है और सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करने के साथ ही एक्स पर भी पोस्ट कर माफी दिये जाने का अनुरोध किया है.

मंत्री शाह ने पत्र की शुरुआत जय हिन्द से की है. पत्र में आगे कहा है कि पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्या से मैं मन से बहुत दुखी और विचलित हूं. मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है. मेरे द्वारा कहे गये शब्दों से समुदाय, धर्म, देशवासियों को दुख पहुंचा है. यह मेरी भाषाई भूल थी. मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति एवं समुदाय को ठेस पहुंचाने, आहत करने का

नहीं था. मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गये शब्दों के लिए पूरी भारतीय सेना से, बहन कर्नल सोफिया से एवं समस्त देशवासियों से पूरी तरह से क्षमाप्रार्थी हूं और पुन: हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं.

इंदौर जिले के मानपुर क्षेत्र में 11 मई को हलमा कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिये गये आपत्तिनजक बयान के बाद ये लगातार तीसरा मौका है, जब शाह ने माफी मांगी है. शाह के मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को होना है. 28 मई को ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी. अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकीं हुई है. यदि सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो भी कमेंट करेगा, वह शाह के मंत्री पद पर बने रहने या नहीं रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा. 11 मई को शाह के आपत्तिजनक बयान के बाद जब ये मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो शाह बैकपुट पर आ गए. इधर भाजपा संगठन ने उन्हें तलब किया और 13 मई को उन्हें संगठन की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई. बाद में 14 मई को जबलपुर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बैंच ने इस मामले को संज्ञान में लिया और शाम तक शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये. उसके बाद मानपुर थाने में शाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया.

सुको ने लगाई थी फटकार

ठीक अगले दिन 15 मई को हाईकोर्ट ने एफआईआर पर सवाल उठाये और उसे बेहद लचर करार दिया, जिसमें उन्हें जमानत का मौका मिल सकता है. इस बीच शाह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी उन्हें फटकार मिली. सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को सुनवाई करने के बाद अगली सुनवाई के लिए 19 मई का दिन तय किया. 19 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने शाह के माफीनामा को नामंजूर कर दिया और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दिये.

> शाह के लिए राहत की बात केवल यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. ये रोक अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा. यदि सुप्रीम कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी के आदेश दिये तो फिर शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. इधर सरकार और संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शाह के बारे में निर्णय करेगी. इस बीच शाह लगातार अज्ञातवास में बने हुए हैं. 13 मई के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आये हैं. यहां तक कि 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट की बैठक में भी वे शामिल नहीं हुए.

दुश्मनों को घर में घुसकर मारा

बोले मुख्यमंत्री डॉ. यादव- लहार में सौ बीघा में लगेंगे उद्योग

नवभारत न्यूज

भिंड. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारे बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था. ऐसे नापाक इरादों वाले आतंकियों को पाकिस्तान की धरा पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना ने सबक सिखाया. यह रणनीति है. यह कुशल नीति है. ये ही देश का शौर्य है. यही हमारे जवानों का साहस है. इस साहस को हम प्रणाम करते हैं.

भिंड के लहार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वसहायता समूहों के सम्मेलन में बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो डकैत होते थे. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो डकैतों का खात्मा कर दिया गया. चंबल में अब कोई डकैत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए डकैत पैदा करती थी. इसका वे चुनाव में फायदा लेते थे. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में चंबल भूमि के वीर जवानों के शौर्य की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि लहार क्षेत्र का युवा देश की रक्षा के लिए कंपटीशन करता है. जहां चंबल की माटी का जांबाज ? जवान खड़ा हो, उस क्षेत्र में दुश्मन देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है.

मुख्यमंत्री ने आलमपुर के सरकारी महाविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर करने की घोषणा की. उन्होंने लहार में 100 बीघा जमीन पर पर उद्योग लगाने का ऐलान किया. उन्होंने मछंड, असवार क्षेत्र का उन्नयन करते हुए नगर पंचायत बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने 117 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन विकास कार्यों में सड़क, बिजली, जलप्रदाय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. इससे पूर्व लहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री का हेलीपेड पर स्वागत किया गया.

विकास कार्य के लिए ज्यादा राशि देंगी सांसद राय

कार्यक्रम में सांसद संध्या राय ने कहा कि इस क्षेत्र ने ही मुझे संसद तक भेजने का रास्ता तय हुआ है. उन्होंने कहा कि मैं सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों की सबसे ज्यादा राशि लहार विधानसभा क्षेत्र पर दूंगी. इस मौके पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के विकास के पहिए पर डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में दौड़ रहा है. मैं चाहता हूं कि सीएम के तौर पर मोहन यादव और लहार क्षेत्र ?के विधायक के तौर पर अम्बरीश जनसेवा करते रहें.

आप विधायक अरोड़ा गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने की कार्रवाई

पंजाब, 23 मई. पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने शुक्रवार को जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा (54) को नगर निगम के पूर्व सहायक नगर योजनाकार सुखदेव वशिष्ठ से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया, जिन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था.

आप प्रवक्ता नील गर्ग ने पुष्टि की कि सतर्कता विभाग ने अरोड़ा के आवास पर छापा मारा था. यह पता नहीं चल पाया है कि छापेमारी के बाद रमन अरोड़ा के आवास से क्या मिला, जिसके कारण

भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई. अरोड़ा ने कथित तौर पर फर्जी नोटिस जारी करने और लक्षित व्यक्तियों से पैसे ऐंठने के लिए वशिष्ठ का इस्तेमाल किया. अरोड़ा के खिलाफ शिकायतों के बाद शुक्रवार सुबह वीबी ने उनके घर पर छापा मारा.

भारत के खिलाफ पाक अधिकारी ने उगला जहर

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की सेना पर आतंकी संगठनों को पालने-पोसने के आरोप लगते रहते हैं. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के खिलाफ जहर उगलते और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं. वीडियो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे.

लड़खड़ा गई है देश की विदेश नीति : राहुल

नयी दिल्ली, 23 मई. लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने पर आरोप लगाया और विदेशमंत्री एस जयशंकर की कार्यशैली पर भी सवाल उठायें।

श्री गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, श्री जयशंकर को यह जवाब देना चाहिए कि कुछ देश पाकिस्तान को भारत के बराबरी पर क्यों रख रहे हैं और एक भी देश पाकिस्तान की निंदा करने में हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है. कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया कि अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भारत,पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति लड़खड़ा गयी है.

गौरतलब है कि श्री ट्रम्प लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत ,पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और वह दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे पर भी मध्यस्थता करने को तैयार हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखा है.

कांग्रेस की ओछी राजनीति देश नहीं स्वीकारेगा : भाजपा

नयी दिल्ली, 23 मई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर आपरेशन सिन्दूर के संबंध में भारतीय सेनाओं को निशाना बना कर सवाल खड़े करने और विदेश यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को लेकर ऐतराज जताने की आलोचना की और कहा कि ऐसे ओछे स्तर की राजनीति को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केन्द्रीय कार्यालय में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को वैश्विक मान्यता दिलाई है. दूसरी ओर, राहुल गांधी ने गैर-जिम्मेदार बयानों से पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, जो राष्ट्रहित के विरुद्ध आचरण है. इन सबके बावजूद, भारत आतंक के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई जारी रखेगा.

पाक विमानों के लिए एयरस्पेस 23 जून तक बंद

नई दिल्ली, 23 मई. भारत ने पाकिस्तान की उड़ानों के लिए नाटोम को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. यह 23 जून, 2025 तक प्रभावी रहेगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत इफेक्ट्स और पाकिस्तानी एयरलाइनों/ ऑपरेटरों द्वारा संचालित / स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई इफेक्ट्स के लिए स्वीकृत नहीं है, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं

दूसरी ओर खराब मौसम के दौरान इंडिगो की फ्लाइट को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करने की खबर सामने आने के एक दिन बाद, पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय विमानवाहकों पर अपने प्रतिबंध को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. भारतीय विमानों और विमानवाहकों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो अब 24 जून की सुबह समाप्त होने वाला है. शुक्रवार को पाकिस्तान के विमानन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नए नोटिस टू एयरमेन के माध्यम से इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि की गई.

> पहलगाम आतंकी हमले और बिगड़ते राजनयिक संबंधों के जवाब में 24 अप्रैल को लागू किए गए प्रारंभिक प्रतिबंध ने भारतीय विमानों और ऑपरेटरों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था. इससे पहले दिन में, भारतीय विमानन नियामक प्राधिकरण डीजीसीए ने कहा कि बुधवार को नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान के दौरान, विमान चालक दल ने अशांति से बचने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी.

पाक को आईएमएफ से सहायता का यह उचित समय नहीं

नयी दिल्ली. भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण के समय पर कड़ी आपत्ति जतायी है और कहा है कि वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल के कारण उसे ऋण जारी करने का यह 'उचित समय नहीं है.'

सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया, ' भारत सैद्धांतिक रूप से आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने का विरोधी नहीं है, लेकिन वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल के कारण उसे ऋण सहायता देने का यह सही समय नहीं है.

3 बार पाक और 10 बार सऊदी गया शहजाद

टांडा (रामपुर), 23 मई. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार टांडा निवासी शहजाद तीन बार पाकिस्तान जा चुका है. एक बार वह पत्नी को लेकर भी गया था. इसके अलावा वह 10 बार सऊदी अरब भी जा चुका है.

शहजाद को एटीएस ने 18 मई को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था. शहजाद पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. साथ ही उसके संबंध आईएसआई से भी होने की बात सामने आई थी. शहजाद ने शुरुआत में

आईएसआई जासूस से लगातार हो रहे खुलासे

परिवार व संपर्क में आए लोगों से पूछताछ

ड्राइविंग भी की. इसके बाद वह तस्करी और फिर जासूसी करने लगा. गिरफ्तारी के बाद उसकी गतिविधियों की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. शहजाद की गिरफ्तारी के बाद से टांडा व रामपुर जनपद पर खुफिया एजेंसियों की निगाह है.

शहजाद शुरुआत में गाड़ी चलाता था, लेकिन जल्द ही उसने कॉस्मेटिक्स, मसाले व कपड़ों की तस्करी शुरू कर दी. इसके बाद पाकिस्तान आना-जाना शुरू हुआ और वह आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आया. इसके बाद उसने भारत में आईएसआई के लिए भारत में काम करना शुरू किया.

दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन | नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते शांति के महत्व को प्रधानमंत्री ने किया रेखांकित

आतंकवाद, माओवादी हिंसा अब बर्दाश्त नहीं : मोदी

नयी दिल्ली, 23 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांति और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को विकास की आवश्यक शर्त बताया है और कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 11 वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना-विकास और शांति के लिए जो काम किए हैं, उससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य आज निवेशकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

श्री मोदी ने शुक्रवार को यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास के विषय पर केन्द्रित दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन- नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते

शांति के महत्व को रेखांकित किया. प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, (उनके प्रति) हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस (रत्ती भर भी बर्दाश्त न करने) की नीति पर चल रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर में विभिन्न संगठनों के साथ पिछले कुछ वर्षों में कई शांति समझौते किए हैं और 10 हजार से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़ कर मुख्य धारा को अपनाया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की उनकी योजना में क्षेत्र के युवाओं के लिए विकास के अवसरों का सृजन सबसे उच्च प्राथमिकता रखता है. उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में हमने पूर्वोत्तर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जो कुछ किया है, वह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि वह क्षेत्र के विकास की एक बड़ी सोच को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधा, हर निवेश की पहली शर्त है. पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत समय तक अभाव में रहा था, लेकिन अब वहां भारी निवेश हुआ है. एक दशक में वहां 11 हजार किलोमीटर के नये राजमार्ग बने हैं, सैकड़ों किलोमीटर के नये रेल मार्ग विकसित हुए हैं, तथा हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गयी है.

> उन्होंने निवेशकों से उस क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए पहले पहुंचने की सलाह देते हुए कहा कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास और व्यापर की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के विकास तथा कोलकाता और कालादान (म्यांमार) बंदरगाह सम्पर्क परियोजना पर काम कर रहा है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के सम्मिलित प्रयासों से पूर्वोत्तर में निवेश का शानदार माहौल बना है. पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता उसकी बड़ी शक्ति है. सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है.

यूनुस जल्द दे सकते हैं इस्तीफा

बांग्लादेश की सेना की नाराजगी बनी वजह

ढाका, 23 मई. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस को लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है.

नाहिद इस्लाम ने मीडिया समूह से कहा, हम आज सुबह से सर (यूनुस) के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं. इसलिए मैं उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था. सर ने भी यही कहा कि वे इस बारे में सोच रहे हैं. उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वे काम नहीं कर सकते. गौरतलब है कि नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार में

शुरुआत में खुद यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं. हालांकि, इसी साल उन्होंने यूनुस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का एलान कर दिया था.

मोहम्मद यूनुस की तरफ से अपना पद छोड़ने की मंशा जाहिर करने की खबरों के बीच यह जानना अहम है कि आखिर बांग्लादेश में अचानक ऐसा क्या बदला है, जिससे देश में सियासी हलचल पैदा हो गई है?